शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 34 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 18 – 25 अगस्त 2025 मूल्य पांच रूपये

क्या कांग्रेस संगठन का गठन ऐसे हो पायेगा?

शिमला/शैल। कांग्रेस संगठन पर अब तक यह फैसला नहीं हो पाया है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा और उसकी कार्यकारिणी का स्वरूप क्या होगा? यह सवाल इसलिये गंभीर और महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी भाजपा और मोदी सरकार से भीड़ते जा रहे हैं उन्हें उसी अनुपात में कांग्रेस शासित राज्यों से सहयोग चाहिये? इस समय देश के तीन ही राज्यों हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें हैं। इनमें हिमाचल में लम्बे अरसे से प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक सारी कार्यकारणीयां भंग चल रही हैं। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं द्वारा सदन में आरएसएस की प्रार्थना का गायन किया जाना कुछ ऐसे संकेत बनते जा रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में सब ठीक नहीं चल रहा है। राहुल गांधी ने गुजरात के एक आयोजन में यह कहा था कि कांग्रेस में भाजपा के सैल कार्यरत है। लेकिन अभी तक इन सैलों को चिन्हित करके बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा सका है। लेकिन राहुल के कथन के बाद अधिकांश कांग्रेसियों को भाजपा के स्लीपर सैल के रूप में देखा जाने लग पड़ा है। इस समय बिहार में वोट चोरी के आरोप पर जिस तरह का जन आन्दोलन खड़ा होता जा रहा है क्या उसी अनुपात में कांग्रेस शासित राज्यों में भी उसी तरह का राजनीतिक वातावरण तैयार होता जा रहा है? तो हिमाचल की स्थिति को देखते हुये कहा जा सकता है कि शायद नहीं। हिमाचल में संगठन की कार्यकारणीयां भंग होने के बाद कुछ अरसे तक यह संकेत उभरते रहे कि नई टीम का गठन भी प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में ही होगा। लेकिन अब यह सन्देश स्पष्ट होता जा रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष भी बदला जायेगा। अभी जिस तरह से वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यालय में आयोजन रखा गया था और उसमें जिस तरह से प्रदेश प्रभारी के सामने ही मुख्यमंत्री सुक्खू और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के समर्थकों में अपने-अपने नेता के पक्ष में नारेबाजी की गयी उससे स्पष्ट हो गया कि प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इस नारेबाजी का प्रतिफल यह रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस कार्यालय से बाहर फील्ड में कहीं नहीं जा पाया है। बल्कि अब तो यह चर्चा भी दबी जुबान में चल पड़ी है कि यह नारेबाजी एक तय योजना के साथ की गयी थी कि इसे फील्ड में न ले जाना पड़े। कांग्रेस कार्यालय में हुई नारेबाजी के बाद संगठन के गठन की बात फिर बैक फुट पर चली गयी है। क्योंकि इस नारेबाजी में पार्टी के अन्दर बन चुकी गुटबाजी पूरी तरह खुलकर सामने आ गयी है। इस तरह की नारेबाजी के चलते कांग्रेस का हाईकमान से आया कोई भी निर्देश व्यवहारिक शक्ल नहीं ले पायेगा। इस समय अगले प्रदेशाध्यक्ष को लेकर चल रही खींचतान में यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू इस पद पर किसी अपने विश्वस्त को ही बैठना चाहते हैं। अध्यक्ष के लिये कोई भी मंत्री अपना मंत्री पद छोड़कर यह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। मंत्रियों के बाद पूर्व मंत्रियों कॉल सिंह ठाकुर और आशा कुमारी भी चर्चाओं के अनुसार इसके लिये सहमत नहीं हो पाये हैं। अब मुख्यमंत्री शायद इस पद के लिये हमीरपुर जिले से विधायक सुरेश कुमार को अपनी पसन्द बना सकते हैं। लेकिन इस नाम पर औरों की सहमति हो पायेगी इसको लेकर संशय है। जब प्रदेश में किसी न किसी कारण से संगठन का गठन ही लटकना चला जायेगा तो हाईकमान को राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रदेश से कितना व्यवहारिक सहयोग मिल पायेगा यह एक सामान्य समझ की बात है। प्रदेश सरकार इस वर्ष के अन्त में होने वाले निकाय चुनावों को टालने में सफल हो गयी है। बहुत संभव है कि किसी तरह पंचायत चुनावो को भी टालने का जुगाड़ कर ही लिया जायेगा। यह चुनाव ही सरकार के लिये एक परीक्षा होने जा रहे थे। जब यह परीक्षा ही टल जायेगी तो और कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है और फिर राष्ट्रीय कार्यक्रमों को फील्ड में ले जाने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है।

रोजगार पर स्वत:विरोधी आंकड़ों में उलझी सरकार

शिमला/शैल। हिमाचल में सरकार ही सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। इसलिए हर राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिये बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का आश्वासन देकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनावों में युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये प्रतिवर्ष एक लाख नौकरियां उपलब्ध करवाने की गारंटी दी थी। पांच वर्षो में पांच लाख नौकरियां दी जानी थी। यह गारंटी अपने में एक बहुत बड़ा वायदा था। जिसका चुनावी परिदृश्य पर असर होना स्वभाविक था और परिणामत: कांग्रेस की सरकार बन गयी। सरकार बनने के बाद इस दिशा में एक मंत्रियों की कमेटी बनायी गयी यह पता लगाने के लिये की सरकार में कुल कितने पद खाली हैं। इस मंत्री कमेटी के मुताबिक सरकार में 70000 रिक्त पद पाये गये। इससे यह उम्मीद बंधी की कम से कम यह 70000 पद तो तुरंत प्रभाव से भर ही लिये जाएंगे। दिसम्बर 2022 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 2024 में विधानसभा में एक प्रश्न के माध्यम से यह पूछा गया था कि अब तक कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया कि 34980 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। लेकिन अभी 15 अगस्त के समारोह में मुख्यमंत्री ने 23191 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने का आंकड़ा परोस दिया। सतपाल सती और विपिन परमार के प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि गत दो वर्षो में विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 5960 पद सृजित किये गये और 1780 पद समाप्त किये गये।

रोजगार पर आये इन आंकड़ों से यह प्रश्न उठना स्वभाविक है कि एक लाख रोजगार प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाने की गारंटी देकर आयी सरकार की इस क्षेत्र में उपलब्धियां क्या हैं? इसी के साथ यह सवाल और खड़ा होता है कि 15 अगस्त के भाषण के लिये मुख्यमंत्री को सामग्री उपलब्ध करवाने वाले तंत्र ने भी इसका ख्याल नहीं रखा की रोजगार पर पहले विधानसभा में क्या आंकड़ा रखा गया है। सदन में रखी जा रही जानकारी की विश्वसनीयता पर तो कांग्रेस विधायक आर.एस.बाली ने भी गंभीर आक्षेप उनके बिजली बिल को लेकर रखे गये आंकड़े पर उठाया है। आंकड़ों की विश्वसनीयता पर ही तो भाजपा विधायक सुधीर शर्मा का विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आया है। जबकि यह माना जाता है कि प्रशासन विधानसभा में जानकारियां उपलब्ध करवाने में विशेष सतर्कता बरतता है। क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर आसानी से न मिल रहा हो उसका जवाब देने के लिए सूचना एकत्रित की जा रही है का विकल्प अपना लिया जाता है।

इस परिदृश्य में यदि यह आकलन किया जाये कि अब तक के कार्यकाल में चुनावों के दौरान बांटी गयी गारंटीयों पर

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल ने सिपुर में पौधरोपण अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का आह्वान किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला जिला के मशोबरा ब्लॉक के सिपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसायटी और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर, राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण का एक सशक्त संदेश देते हुए देवदार का पौधा रोपित किया।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश अपनी हरी-भरी घाटियों, बर्फ से ढकी चोटियों और नदियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में, राज्य ने भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बादल फटने जैसी गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। उन्होंने कहा कि धरती पर घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाती हैं। वनों का अनियंत्रित कटान, जल संसाधनों का प्रदूषण और अनियोजित विकास के कारण पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत पौधरोपण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। यह एक जीवन रक्षक पहल है। उन्होंने कहा कि पौधरोपण के माध्यम से हम मिटी और जल का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करते हैं।

इस अवसर पर राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मशोबरा के विद्यार्थियों द्वारा प्रधानाचार्या अनीता गुप्ता के मार्गदर्शन में लगभग 120 पौधे लगाए गए। वन अधिकारियों, रेडक्रॉस सदस्यों और स्थानीय लोगों ने भी पौधरोपण अभियान में भाग लिया।

इससे पहले, राज्यपाल ने सिपुर स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की।

राज्यपाल ने काव्य संकलन 'दायरों से परे' का विमोचन किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में काव्य संकलन 'दायरों से परे' का विमोचन किया। यह काव्य संकलन प्रसिद्ध कवि और राजकीय महाविद्यालय आनी के प्रधानाचार्य डॉ. कुंवर दिनेश सिंह द्वारा सम्पादित किया गया है। इस संकलन में 11 प्रतिष्ठित समकालीन हिन्दी कवियों की 67 कविताएं, गज़लें और लघु कथाएं शामिल हैं, जिनमें डॉ. गिरिराज शरण अग्रवाल, हरिराम समीप, गिरिश पंकज, रामेश्वर कम्बोज हिमांशु, अशोक शाह, डॉ. शिवजी श्रीवास्तव, सुबोध नीरव, सुकेश साहनी, हरभगवान चावला, आनन्द नीमा और स्वयं डॉ. सिंह शामिल हैं।

इस संस्करण में संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ फैलो डॉ. लाल चन्द गुप्ता 'मंगल' और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष द्वारा लिखी गई ज्ञानवर्द्धक प्रस्तावना भी शामिल है।

राज्यपाल ने संपादक और अन्य कवियों की रचनात्मक अभिव्यक्तियों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की साहित्यिक कृतियां समाज के सांस्कृतिक ताने-बाने को समृद्ध करती हैं। उन्होंने कहा कि 'दायरों से पार' काव्य संकलन पाठकों विशेषकर युवा पीढ़ी को हिन्दी साहित्य की गहराई और विविधता को समझने और सराहने के लिए प्रेरित करता है।

डॉ कुंवर दिनेश सिंह को हिमाचल प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई साहित्यिक सम्मान मिल चुके हैं। उन्होंने कविता, लघु कथा, हाइकू, समीक्षा और साहित्यिक आलोचना की 35 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनके कार्य पूरे भारत और विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाए और शोध किए जाते हैं।

राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय जागरूकता और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित

शिमला/शैल। वरिष्ठ नागरिकों के ज्ञान, अनुभव और योगदान के सम्मान में कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस-2025 का आयोजन किया गया। क्लेरेनियोन्ट बिल्डिंग, शिमला के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में 71 पेंशनभोगियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में विशेष रूप से नियंत्रक संचार लेखा दीपक कुमार, उप नियंत्रक मयंक नेगी, उप नियंत्रक सुषमा नेगी सहित समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर नियंत्रक संचार लेखा दीपक कुमार ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे अनुभव और ज्ञान के भंडार हैं। विभाग सदैव उनके कल्याण एवं सुविधा हेतु तत्पर है और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे।

वरिष्ठ नागरिक दिवस पर आयोजित वित्तीय साक्षरता सत्र में पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय योजनाओं एवं ऑनलाइन बैंकिंग पर SBI अधिकारियों द्वारा जागरूक किया गया। बैंक के अधिकारियों ने पेंशनभोगियों को वित्तीय निवेश और शेयर मार्केट संबंधी जानकारी भी दी। इसके बाद सभी पेंशनभोगियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें रक्त संबंधी सामान्य टेस्ट के अलावा आंख, दांत, फेफड़े, ECG आदि की जांच की गई। परिसर में आयुष चिकित्सा एवं योग कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। जिसमें वृद्धावस्था में स्वास्थ्य एवं कल्याण, आयुर्वेदिक आहार योजना तथा योगाभ्यास पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया। आधुनिक समय में मांग को देखते हुए विशेषज्ञों द्वारा पेंशनरों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। पेंशनरों को साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मोबाइल एप के प्रयोग की जानकारी दी गई। इसके अलावा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र स्वयं बनाने की प्रक्रिया पर विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जागरूकता संदेश दिया और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित किया साथ ही पौधे लगाये गये।

कार्यक्रम में भाग लेने वाले पेंशनभोगियों ने विभाग द्वारा किये गये इस आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल से उन्हें समाज में सम्मान और अपनत्व का अनुभव होता है। साथ ही, उन्होंने विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ नागरिकों को विभागीय अधिकारियों एवं स्टाफ ने शुभकामनाएं दीं और उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की।

सद्भावना दिवस पर उपायुक्त कांगड़ा ने दिलाई शपथ

शिमला/शैल। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना दिवस शपथ दिलाई और पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि सद्भावना दिवस का मूल उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारे, सौहार्द तथा राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि हमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र अथवा सम्प्रदाय से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करना चाहिए।

उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आहवान किया कि वे अपने कार्यक्षेत्र में पारदर्शिता, ईमानदारी और समर्पण की भावना से कार्य करते हुए समाज में शांति और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा दें। उपायुक्त ने कहा कि आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार की हिंसा और भेदभाव का विरोध करेंगे तथा सदैव सौहार्द और एकता की राह पर चलेंगे।

इस अवसर पर एडीसी विनय कुमार, एसडीएम मोहित रत्न सहित विभिन्न अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

इसके अतिरिक्त जिला के विभिन्न उपमंडल कार्यालयों में भी सद्भावना दिवस पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने शपथ ली और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

कांगड़ा जिला में भूकंप सुरक्षा एवं तैयारी को लेकर विशेष निर्देश जारी

शिमला/शैल। भूकंप की दृष्टि से कांगड़ा जिला की भौगोलिक संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी संस्थानों एवं विभागों को भूकंप सुरक्षा और आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारियों को तुरंत मजबूत करने के निर्देश जारी किए हैं।

निर्देश जारी करते हुए जिला दण्डाधिकारी हेमराज बैरवा ने कहा कि जिला के समस्त संस्थान समयबद्ध ढंग से कदम उठायें। उन्होंने कहा कि समस्त संस्थान ड्रॉप, कवर और होल्ड भूकंप सुरक्षा अभ्यास करें। सभी स्टाफ, विद्यार्थी एवं कर्मचारियों के लिए यह अभ्यास दो दिनों के भीतर करवाना अनिवार्य है। इस संबंध में की गई गतिविधियों की रिपोर्ट एवं तस्वीरें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मोबाईल नम्बर 9459485243 पर भेजी जायें।

हेमराज बैरवा ने कहा कि सभी संस्थान एक सप्ताह के भीतर अपनी संवेदनशील परिसंपत्तियों, महत्वपूर्ण भवनों एवं लाइफ लाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर का त्वरित सुरक्षा ऑडिट करें ताकि जोखिमों एवं कमियों की पहचान की जा सके। इसके साथ ही भूकंप सुरक्षा से संबंधित भवनों की समीक्षा कर किसी भी संरचनात्मक कमी को रिपोर्ट किया जाये।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रतिक्रिया एवं तैयारी प्रणाली को मजबूत करना है। समस्त संस्थान आपातकालीन संचार प्रोटोकॉल अपडेट करने के साथ ही आपदा की स्थिति में निकासी योजनाओं का भी अभ्यास करें, इसके साथ ही प्राथमिक उपचार, अग्नि सुरक्षा और बचाव उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये और संस्थान में सुरक्षित एकत्रीकरण स्थलों की पहचान कर प्रमुख कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि संस्थान में जागरूकता गतिविधियां चलाएं ताकि प्रत्येक सदस्य को यह जानकारी हो कि भूकंप से पहले, दौरान और बाद में सुरक्षित तरीके से कैसे कार्य करना है। उन्होंने कहा कि यह सभी कार्य अनिवार्य रूप से पूरे किए जाएं और एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कर रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजी जाए।

ढाबों में ओवरचार्जिंग पर कड़ी निगरानी, शिकायत पर होगी सख्त कारवाई

शिमला/शैल। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन के निर्देश पर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीमों ने 25 जगहों का निरीक्षण किया और 12 हजार रुपये के चालान किये। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिले के ढाबों, रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठानों में बिकने वाले पके भोजन, दही आदि जैसी वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य तय किए गए हैं। कोई भी विक्रेता निर्धारित मूल्य अथवा तय अधिकतम लाभ सीमा से अधिक राशि नहीं वसूल सकता। इसी प्रकार पैक किए गए सामान पर अंकित मूल्य से अधिक कीमत लेना भी नियमों के तहत वर्जित है।

उन्होंने बताया कि फोरलेन बंद होने के कारण ढाबों में ओवरचार्जिंग की शिकायतों को रोकने के लिए जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए निरीक्षक खाद्य आपूर्ति की अध्यक्षता में दो विशेष टीमें गठित की गई हैं। एक टीम मंडी से औट के बीच और दूसरी टीम नागचला क्षेत्र में, जहां कुल्लू जाने वाले वाहन बड़ी संख्या में रुकते हैं, लगातार गश्त करेंगी। यह टीमें ढाबों पर अधिक मूल्य वसूलने की शिकायत पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कारवाई करेंगी ।

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन ने ढाबों और पर्यटन इकाइयों में ओवरचार्जिंग रोकने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के साथ पर्यटन विभाग तथा राजस्व अधिकारियों को भी फील्ड में तैनात किया है। ये अधिकारी ढाबा संचालकों और पर्यटन इकाइयों के मालिकों के साथ बैठक कर उन्हें स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि भोजन, पानी अथवा शौचालय उपयोग के लिए किसी भी स्थिति में अतिरिक्त शुल्क न वसूला जाये।

उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि यदि कहीं भी ओवरचार्जिंग की शिकायत हो तो एसडीएम सदर मंडी का मोबाइल नंबर 9418191215, एसडीएम बालीचौकी का मोबाइल नंबर 9317207037, खाद्य निरीक्षक का मोबाइल नंबर 8219964007 और सहायक नियंत्रक का मोबाइल नंबर 9015344538 या जिला आपातकालीन संचालन केंद्र मंडी का टोल फ्री नंबर 1077 तथा लैंडलाइन नंबर 01905-226201, 226202 और 226203 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पाजंलि अर्पित की। उन्होंने लोगों से राजीव गांधी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने और उनके सिद्धांतों को अपनाने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी को 'आधुनिक भारत के निर्माता' के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति राजीव गांधी की दूरदृष्टि का परिणाम है, जिससे आज के युवा लाभान्वित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की सोच को आगे बढ़ाते हुए सोनिया गांधी ने राज्यसभा संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक पारित करवाया।

इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और सद्भाव की शपथ भी दिलाई।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ कर्नल धनीराम शांडिल, कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, उपाध्यक्ष विनय कुमार, उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, विधायक मोहन लाल ब्राक्टा, संजय अवस्थी, अजय सोलंकी, विवेक कुमार, नीरज नैफ्यर और मलेन्द्र राजन, राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेन्द्र श्याम, महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, प्रदेश कांग्रेस को-इंचार्ज विधित चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

श्री ज्वाला माता मंदिर का 100 करोड़ से होगा सौंदर्यीकरण:उप मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को परिवार सहित अपनी कुलदेवी मां श्री ज्वाला जी मंदिर में माथा टेका और विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और शांति की कामना की। इस अवसर पर उनकी बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री और बहन भी उनके साथ मौजूद रहीं।

अग्निहोत्री ने मां ज्वाला से प्रदेश में खुशहाली, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा तथा जनसेवा के अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाने की शक्ति प्रदान करने का आशीर्वाद मांगा। मंदिर कमेटी की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 100 करोड़ रुपये की लागत से श्री ज्वाला माता मंदिर का भव्य सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलें, पारंपरिक पूजा पद्धति में गुणवत्ता लायी जाये और मंदिरों का विकास डिजिटल व व्यवस्थित रूप से हो।

इसके उपरांत उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपनी बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री और बहन के साथ माता श्री बगलामुखी मंदिर भी पहुंचे और यहां भी विधिवत शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया।

धर्मशाला रोपवे परियोजना की सभी गतिविधियां अस्थायी रूप से निलंबित

शिमला/शैल। उपायुक्त कांगड़ा एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने धर्मशाला रोपवे परियोजना के समीप भूस्खलन की घटना के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा एवं संभावित जोखिम को देखते हुए तात्कालिक प्रभाव से रोपवे की सभी गतिविधियों को अस्थायी रूप से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।

आदेश में कहा गया है कि उपमंडलाधिकारी (नागरिक) धर्मशाला की रिपोर्ट के अनुसार, पिलर संख्या 5 के समीप भूस्खलन हुआ है, जिससे रोपवे संचालन यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 एवं 34 के अंतर्गत जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।

उपायुक्त ने रोपवे संचालन एजेंसी को आदेशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उपमंडलाधिकारी (नागरिक) धर्मशाला को एक तकनीकी समिति गठित करने के लिए कहा गया है, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के भू-वैज्ञानिक विशेषज्ञ, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि एवं नगर निगम धर्मशाला को शामिल किया जाएगा। यह समिति दो दिनों के भीतर स्थल का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

उपायुक्त ने कहा कि प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही रोपवे गतिविधियों को निलंबित रखने या पुनः प्रारंभ करने संबंधी निर्णय लिया जाएगा। उपायुक्त ने जिला पुलिस अधीक्षक एवं उपमंडलाधिकारी (ना.) धर्मशाला को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

भारत-चीन शिपकी-ला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार खोलने पर सहमत हुए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत और चीन तीन निर्दिष्ट व्यापारिक बिंदुओं-लिपुलेख, शिपकी-ला और नाथू-ला दर्रों से सीमा व्यापार फिर खोलने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्ष 2026 से कैलाश पर्वत, गंग रेनपोछे और मानसरोवर झील की तीर्थयात्रा जारी रखने और इसके विस्तार पर भी सहमत हुए हैं।

हिमाचल सरकार शिपकी-ला (किन्नौर) के माध्यम से चीन के साथ व्यापार बहाल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी, जो हाल ही में भारत की यात्रा पर थे, ने विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने इस बैठक में भारत और चीन के बीच व्यापार फिर शुरू करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

यह सफलता ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण संभव हुई है जिन्होंने केंद्र सरकार से ऐतिहासिक भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग बहाल करने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से चीन के साथ इस मामले को उठाया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार फिर से शुरू करने पर आम सहमति बनी है। राज्य सरकार कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए अब केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएगी।

केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि भारत सरकार ने तीनों निर्दिष्ट बिंदुओं शिपकी-ला (हिमाचल प्रदेश), लिपुलेख (उत्तराखंड) और नाथू ला (सिक्किम) से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए चीन के साथ चर्चा शुरू कर दी है, जो कोविड-19 महामारी के कारण 2020 से बंद था।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि शिपकी-ला, जो कभी प्रसिद्ध सिल्क रूट का हिस्सा था और जिसे वर्ष 1994 के भारत-चीन द्विपक्षीय समझौते के तहत सीमा व्यापार बिन्दु के रूप में औपचारिक रूप दिया गया था, ने ट्रांस हिमालयी आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

व्यापार के अतिरिक्त, राज्य सरकार को शिपकी-ला के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर शुरू करने के संबंध में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। मुख्यमंत्री ने केंद्र को भेजे पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला है कि गरटोक होते हुए दार्चेन और मानसरोवर को जोड़ने वाला शिपकी-ला मार्ग तिब्बत की तरफ से तुलनात्मक रूप से छोटा है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर और पूह होते हुए शिपकी-ला तक पहले से ही सड़क मार्ग मौजूद है, जिससे यात्रा के लिए आवश्यक आधार शिविर और सहायक बुनियादी ढांचा विकसित करना संभव हो गया है।

केंद्रीय विदेश मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में बताया है कि पांच साल के अंतराल के बाद लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड) और नाथू ला दर्रा (सिक्किम) से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू हो गई है। शिपकी-ला को एक अतिरिक्त मार्ग के रूप में जोड़ने की पहल भी कामयाब हुई है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि पारंपरिक सीमा व्यापार पुनः स्थापित होने से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन, सांस्कृतिक आदान- प्रदान और आर्थिक विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे।

मुख्यमंत्री ने चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में राज्य की इन प्रमुख समस्याओं को प्राथमिकता देने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत भरमौर पांगी में विकसित होंगे होम स्टे:मुकेश रेपसवाल

शिमला/शैल। उपायुक्त चम्बा मुकेश रेपसवाल ने कहा कि भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गांवों में होम स्टे विकसित किए जाएंगे। वे राष्ट्रीय सूचना केंद्र में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

उन्होंने बताया कि जिला के जनजातीय क्षेत्रों भरमौर और पांगी में होम स्टे विकसित करने के उद्देश्य से पर्यटन संभावित गांवों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। प्रत्येक क्लस्टर में 4 से 5 गांव शामिल होंगे और प्रत्येक क्लस्टर से 6 से 10 आवेदनों को स्वीकृत किया जाएगा।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनजातीय क्षेत्रों में विकसित किए जाने वाले होम स्टे की औपचारिकताएं तय समय सीमा के भीतर पूर्ण की जाएं। उन्होंने बताया कि नए होम स्टे निर्माण के लिए 5 लाख और पुराने होम स्टे के मरम्मत कार्य के लिए 3 लाख की धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

इस अवसर पर आवासीय आयुक्त पांगी रमन घरसंगी तथा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर कुलबीर सिंह राणा वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। वहीं जिला पर्यटन विकास अधिकारी राजीव मिश्रा और नोट ऑन मैप से मनुज शर्मा भी उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें लोग:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला चम्बा की मणिमहेश यात्रा के दौरान दो श्रद्धालुओं के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवारजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

खराब मौसम के कारण मणिमहेश यात्रा को अस्थाई तौर पर स्थगित किया गया है। इसके अतिरिक्त पठानकोट और जम्मू-कश्मीर के डोडा के जिला उपायुक्तों से अनुरोध किया गया है कि मौसम की स्थिति सामान्य होने तक तीर्थयात्रियों को संबंधित जिलों में ही रोककर रखें।

प्रदेश में जारी भारी बारिश के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने लोगों से किसी भी आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए नदियों और नालों के पास न जाने का आग्रह किया है। मौसम विभाग द्वारा राज्य में आगामी 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का लोगों को पालन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने सभी जिला प्रशासन को भूस्खलन, सड़क अवरोध और अचानक बाढ़ की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ताकि लोगों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े और आवश्यक सेवाओं का सुचारू संचालन भी सुनिश्चित किया जाए।

युवा पुरस्कार के लिए 31 अगस्त तक करें आवेदन

शिमला/शैल। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2024 के लिए 31 अगस्त 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार उन युवाओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

यह जानकारी उपनिदेशक मेरा युवा भारत कार्यालय, ध्रुव डोगरा ने बताया कि इच्छुक युवा खेल मंत्रालय भारत की बेवसाइट https://awards.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी युवा समाज में बदलाव ला रहे हैं, किसी क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं, या युवाओं के लिए प्रेरणा बने हैं, तो अब पूरा देश आपकी कहानी जानेगा।

उन्होंने कांगडा के युवाओं से आग्रह है कि वे इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए ऑनलाइन आवेदन करें और कांगड़ा जिले का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए मेरा युवा भारत- कांगड़ा, जवाहर नगर, धर्मशाला कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में संपर्क कर सकते हैं।

श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

अब जेल से सरकार नहीं चलेगी–कुछ सवाल

अब सरकार जेल से नहीं चलेगी। मोदी सरकार ने इस आश्य का संविधान संशोधन विधेयक इस मानसून सत्र में लाने का प्रयास किया है। जैसे ही यह विधेयक गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में रखा तो उस पर जिस तरह की प्रतिक्रिया विपक्ष की सामने आयी उससे यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपना पड़ गया। प्रवर समिति इस पर विचार विमर्श करके पुनः सरकार को सौंपेगी और तब संभव है कि यह विधेयक पारित हो जाये। प्रधानमंत्री मोदी इस प्रस्तावित विधेयक को जिस तरह से जनता में रख रहे हैं उससे सरकार की नीयत और नीति दोनों पर ही कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए इस पर एक व्यापक बहस की आवश्यकता हो जाती है। स्मरणीय है कि 2014 में जब नरेन्द्र मोदी ने अन्ना आन्दोलन के प्रतिफल के रूप में सत्ता संभाली थी तब उस आन्दोलन के मुख्य बिन्दु ही भ्रष्टाचार और काला धन थे। इन्हीं की जांच के लिये लोकपाल की मांग इस आन्दोलन का मुख्य मुद्दा बन गया था। भ्रष्टाचार के आरोप का आधार सी.ए.जी. विनोद राय की 2G स्पेक्ट्रम पर आयी रिपोर्ट थी। लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार होने का आंकड़ा इस रिपोर्ट में परोसा गया था। काले धन पर बाबा रामदेव के ब्यानों के आंकड़े थे। आरोप गंभीर थे और देश ने इन्हें सच मानकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। हालांकि लोकपाल का मसौदा डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ही पारित कर गयी थी। तब मोदी भाजपा ने देश से वायदा किया था कि संसद और विधानसभाओं को अपराधियों से मुक्त करेंगे। उस वातावरण में कांग्रेस और अन्य दलों से कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया था।

उस परिदृश्य में सरकार बदल गयी। विनोद राय की रिपोर्ट पर जांच चली और विनोद राय ने अदालत में शपथ पत्र देकर ब्यान दिया कि उन्हें गणना करने में चूक लगी थी और ऐसा कोई घपला हुआ ही नहीं था। इस ब्यान के बाद विनोद राय को बी.सी.सी.आई. में एक बड़ा पद दे दिया गया और जनता भ्रष्टाचार के इस सनसनीखेज आरोप को भूल गयी। यह मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कारवाई थी। काले धन के आंकड़ों पर बाबा रामदेव चुप्पी साध गये। स्वयं सुप्रीम कोर्ट की प्रताड़ना के एक मामले में शिकार हुये। आज काले धन का आंकड़ा नोटबंदी के बावजूद पहले से दो गुना हो चुका है। विपक्ष के जितने भी नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे ई.डी और सी.बी.आई. ने कारवाई की वह सब भाजपा में जाकर पाक साफ हो गये हैं। आज शायद दल बदल कर भाजपा में आये नेताओं का आंकड़ा संसद में मूल भाजपाइयों से बड़ा है। ई.डी. आयकर और सी.बी.आई. प्रताड़ना के हथियार मात्र बनकर रह गये हैं। ई.डी. की शक्तियों का किसी समय अनुमोदन करने वाला सुप्रीम कोर्ट ही आज उस पर सबसे गंभीर सवाल उठाने लग गया है। संसद और विधानसभाओं को अपराधियों से मुक्त करवाने के वायदे का प्रतिफल आज यह है कि भाजपा में ही अपराधियों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई है। इस परिदृश्य में यह आशंका एकदम जायज हो जाती है कि किसी भी मंत्री/मुख्यमंत्री के पीछे सी.बी.आई./ई.डी. लगाकर उसे गिरफ्तार करवा दो और तीस दिन तक जमानत न होने दो और अपने आप सत्ता से व्यक्ति बाहर हो जायेगा। अरविन्द केजरीवाल और सत्येंद्र जैन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि इस संशोधन से तीन माह के भीतर ही देश विपक्ष रहित हो जायेगा।

आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग जिस तरह से वोट चोरी के पुख्ता दस्तावेजी प्रमाणों के साथ आरोपों में घिर चुके हैं उससे बाहर निकलने के लिये यह प्रस्तावित संशोधन एक बड़ा सहज हथियार प्रमाणित होगा। लेकिन आज वोट चोरी का आरोप जिस प्रामाणिकता के साथ जन आन्दोलन की शक्ल लेता जा रहा है उसके परिदृश्य में आज हर आदमी इस पर गंभीरता से विचार करने लग गया है। क्योंकि 2014 और 2019 में जो वायदे देश के साथ किये गये थे आज उनकी प्रतिपूर्ति एक जन सवाल बनती जा रही है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का यह सबसे बड़ा कड़वा सच है कि देश में अस्सी करोड़ लोग अपने लिये दो वक्त की रोटी के लिये भी सरकार पर निर्भर बना दिये गये हैं। आज अमेरिका, रूस और चीन के साथ हमारे आयात–निर्यात के आंकड़े ही इसका प्रमाण है कि हम उत्पादन में कहां खड़े हैं। सभी जगह व्यापार असन्तुलन है। इस परिदृश्य में इस तरह के संशोधनों से विपक्ष की आवाज को बन्द करने के प्रयासों का प्रतिफल सरकार के अपने लिये घातक होगा।

इस्लाम की मूल अवधारणा में छुपा है एक लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना

गौतम चौधरी

इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान की आयतों का जब हम निचोड़ निकालते हैं तो हमें धार्मिक और सामाजिक चिंतन से ज्यादा यह एक राजनीतिक समावेशी समाज के निर्माण की संकल्पना जान पड़ता है। इस्लाम के अंतिम पैगंबर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहे व आलिहि व सल्लम मोहम्मद पैगंबर मक्का में, यहां तक कि काबा के परिसर में भी कुरआन के उपदेश देने लगे और उन्हें सुनने वालों की तादाद धीरे–धीरे बढ़ने लगी तो तत्कालीन अरब–समाज में हलचलें पैदा हुई। अगर उनके संदेश का स्वरूप गुढ रहस्यवाद और आध्यात्मिक ही रहता तो पारंपरिक अरबी समाज और सत्ता में बैठे रसूख़दारों को इससे अधिक आपत्ति न होती, किन्तु उनके कानों पर तब जूँ रेंगीं जब मोहम्मद के उपदेश सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक आयामों में प्रवेश करने लगे।

मक्का के तत्कालीन बहुदेववादी और मूर्तिपूजक रसूख़दारों को मोहम्मद के एकेश्वरवाद के उपदेश ने जितना तंग किया, उससे ज्यादा वो मोहम्मद के राजनैतिक ब्यानों से परेशान हो रहे थे। मोहम्मद ग़ैर–बराबरी और नाइंसाफ़ी की ज़ोरदार मुख़ालिफ़त कर रहे थे, मज़लूमों और ख़ासकर यतीमों की मदद करने का विचार उनके दिल के क़रीब था। उनके उपदेशों से यह जान पड़ता है कि वे धन–संग्रह की सरमायेदारी प्रवृत्तियों के विरोधी थे और ज़कात की समर्थक थे। तत्कालीन अरब–समाज के नामी–गिरामियों को मोहम्मद की इन बातों में बग़ावत की बू आने लगी। यही कारण है कि तत्कालिन अरबी पारंपरिक समाज ने मोहम्मद की मुख़ाल्फत प्रारंभ कर दी।

ज़रा कुरआन की इन आयतों पर ग़ौर फ़रमाइये :

''जिन्होंने सच्चाई से पीठ फेरी और दौलत इकट्ठा करके उसको ताले में बंद कर दिया, उनको कुरआन बुलाकर कहती है...'' (70: 17–18) जो फ़कीरों और मज़लूमों को ज़कात देते हैं... (70: 24–25)

''और हम ये चाहते थे कि कमज़ोरों का साथ दें और उन्हीं को वारिस बनाएं।'' (28: 5)

''जो दौलत जमा करते हैं और अपने पैसों की मुसलसल गिनती करते फिरते हैं, उन्हें क्या लगता है वो दुनिया–फ़ानी में हमेशा जीते रहेंगे?'' (104:2–3)

''फ़ुज़ूलख़र्च मत करो। यक़ीनन, ख़ुदा बेजा ख़र्च करने वालों को पसंद नहीं करता।'' (6:141)

उक्त कुरानी आयतों के कारण ही वामपंथी मुस्लिमों ने इस्लामिक व्यवस्था को कल्याणकारी राज व्यवस्था का पहला संगठित स्वरूप बताया है। इन्हीं तमाम आयतों के हवाले से इस्लामिक–सोशलिज्म के विचार की स्थापना की गयी और यह रेखांकित किया गया कि वेलफ़ेयर–स्टेट का विचार इस्लाम के मूल में है।

मोहम्मद का यह संदेश कि ख़ुदा के सामने सब बराबर हैं, ज़ात, नस्ल और दौलत की बुनियाद पर किसी में कोई ऊंच–नीच नहीं है, उस वक्त के अरब–समाज के हाशिये के लोगों के दिलों को छू गया था। इससे इस्लाम की तत्कालीन अरब–समाज की परिस्थितियों में एक क्रांतिकारी भूमिका परिलक्षित होती है। इतिहासकार गिबन ने तो इस्लाम के उदय को ''एक ऐसी अविस्मरणीय क्रांति'' बताया, जिसने ''दुनियाभर के मुल्कों के राष्ट्रीय–चरित्र पर स्थायी प्रभाव छोड़ा।'' महान साम्यवादी चिंतक मानवेन्द्र नाथ राय ने कहा है कि ''इस्लाम का उदय धार्मिक दमन के विरुद्ध पीड़ित लोगों के संरक्षण के रूप में हुआ था।'' इलहाम से पहले का ख़ुद मोहम्मद का जीवन–चरित्र इसकी मिसाल देता है कि कैसे वो कारोबार में ईमानदारी को सर्वोच्च मूल्य मानते थे, चीज़ों को वाजिब दामों पर बेचने की हिमायत करते थे और मुनाफ़े का हिस्सा ज़रूरतमंदों को तक़सीम कर देने की बात करते थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा करके भी दिखाया, जबकि उन दिनों उनके पास दौलत नहीं थे।

मोहम्मद के इस विचार के कारण मक्का के ताक़तवर रसूख़दारों के द्वारा अबू–तालिब पर दबाव बनाया जाने लगा कि वो मोहम्मद को हिदायत दें या हाशिम कुनबे से निकाल बाहर कर दें। कुनबे से निकाल बाहर कर देने का मतलब उस ज़माने में यह था कि अगर तब ज़ात–बदर शख़्स का क़त्ल कर दिया जाए तो उसकी मौत का इंतक़ाम लेना उसके कुनबे के लिए फ़र्ज़ नहीं होगा। जब अबू–तालिब ने मोहम्मद को समझाने के लिए बुलाया और उनसे अर्ज़ किया कि ऐसे खुलकर ये तमाम बातें ना बोलें, जिससे खुद के समाज में परेशानी हो। तब मोहम्मद ने जवाब दिया– ''अगर मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे में चाँद रख दिया जाए, तब भी मैं हक़ की राह से पीछे ना हटूंगा, फिर चाहे मेरा क़त्ल ही क्यों ना कर दिया जाए!''

इतिहासकार अल–तबरी का ब्यान है कि ऐसा कहते हुए मोहम्मद की आंखें डबडबा गई और वो दरवाज़े की ओर बढ़े। तब अबू–तालिब ने रूंधे गले से उन्हें रोका और कहा कि चाहे जो हो जाए, मैं कभी तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। उन्होंने ताउम्र ये वादा निभाया भी, हालांकि वो ख़ुद बुतपरस्त थे और उन्होंने ख़ुद कभी इस्लाम क़ुबूल नहीं किया।

मोहम्मद को डराने–धमकाने और लालच देकर ख़रीदने तक की कोशिशें की गई, लेकिन सब नाकाम रहीं। इतिहास गवाह है कि उस दौर की तमाम ज़िल्लत का सामना मोहम्मद ने सब्र, ख़ामोशी और यहां तक कि पूरी अहिंसा के साथ किया। एक बार तो मोहम्मद दुआ में बैठे थे और अबू–जहल नाम का उनका एक विरोधी उनके सामने खड़े होकर उन्हें गालियां बक रहा था। इस तरह के दृश्यों ने आम लोगों के मन में मोहम्मद के प्रति हमदर्दी बढ़ा दी। जैसा कि लेज़्ली हैज़्लटन ने मोहम्मद की बायोग्राफ़ी में लिखा है –''मोहम्मद का ज़ोर कुरआन के संदेश पर था, लेकिन उनके विरोधियों का ज़ोर मोहम्मद पर था। मोहम्मद ने बार–बार कहा था कि मैं सब लोगों से अलग नहीं हूं, लेकिन उनके विरोधियों ने उनकी मुख़ालिफ़त कर–करके उन्हें आमजन की नज़र में विशिष्ट बना दिया।''

यही वो दौर था, जब मोहम्मद के समर्थकों और इस्लाम क़बूल करने वालों में कुछ अहम नाम जुड़े और जिन्होंने मोहम्मद की तरफ़ शक्ति–संतुलन को झुका दिया। इनमें कुछ दूरदर्शी रणनीतिकार और दुरदर्शी योद्धा भी थे, जो आगे चलकर इस्लाम की बुनियाद को मज़बूत बनाने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे रणनीतिकार सहाबा कहलाए। इसमें अहम नाम, हजरत अबू–बकर सिद्दकी, हज़रत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली का नाम सुमार है। इन सहाबाओं ने इस्लाम की बुनियाद को इतना मजबूत कर दिया कि वह आज तक दुनिया को प्रकाश और प्रभाव प्रेषित कर रहा है।

विकसित भारत के लिए मोदी का सुधारों का ब्रह्मास्त्र

हरदीप एस पुरी
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री

मुझे अपने स्कूल के दिनों से ही 15 अगस्त के भाषणों में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का 12वें स्वतंत्रता दिवस का भाषण अभूतपूर्व और असाधारण था। इसमें विकसित भारत के पथ पर भारत की गति बढ़ाने के दिशा में सीधे तौर पर लक्षित – ब्रह्मास्त्र – अर्जुन का अकाटड पौराणिक अस्त्र – छोड़ा गया।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त असामान्य उथल – पुथल के दौर के बीच, विकसित भारत का सपना संजोए भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में निरंतर आगे बढ़ना जारी रखे हुए है। यह भाषण केवल अपनी व्यापकता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने दायरे साहसिक, भविष्योन्मुखी और 1.4 बिलियन लोगों के भाग्य को नया आकार देने में सक्षम अगली पीढ़ी के सुधारों और उस विजन के प्रति स्पष्टता के लिए भी उल्लेखनीय है, जिसका यह राष्ट्र इससे पहले कभी साक्षी नहीं रहा।

उदाहरण के लिए, डिजिटल इंडिया स्टैक को ही लें, यूपीआई दुनिया के आधे रीयल – टाइम लेनदेन के लिए उत्तरदायी है और साल के अंत तक होने वाला, पहली मेड – इन – इंडिया चिप का लॉन्च, वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की अग्रणी स्थिति को दर्शाता है। ऐसे समय में जब राष्ट्रों की नियति सेमीकंडक्टर निर्धारित करते हैं, महत्वपूर्ण तकनीकों पर संप्रभुता का भारत का यह दावा किसी डिजिटल स्वराज से कम नहीं है।

ऊर्जा सुरक्षा लंबे समय से भारत के विकास की राह की सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है। दशकों तक, झिझक और नो गो क्षेत्रों ने अन्वेषण को बाधित किया और आयात पर निर्भरता बढ़ा दी। वह दौर अब बीत चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने ईईजेड में नो गो क्षेत्रों को लगभग 99% तक कम कर दिया है, जिससे 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ईएंडपी के लिए मुक्त हो गया है। ओएएलपी के साथ, इसने भारतीय और वैश्विक दिग्गजों, दोनों के लिए समान रूप से एक विशाल क्षेत्र खोल दिया है। हमारे हाइड्रोकार्बन बेसिन अब निष्क्रिय नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति के लिए उपयोग में लाए जाएंगे।

लाल किले की प्राचीर से घोषित ऐतिहासिक राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में एक महत्वाकांक्षी दूरदर्शी एजेंडा निर्धारित करता है। इस मिशन का लक्ष्य लगभग 40 वाइल्डकैट कुओं की ड्रिलिंग के माध्यम से 600 – 1200 मिलियन मीट्रिक टन तेल और गैस भंडारों का पता लगाना है। पहली बार, बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक भारत अपनी जटिल अपतटीय सीमाओं को व्यवस्थित रूप से खोलेगा, एक ऐसे ढांचे के साथ जो सूखे कुओं की स्थिति में 80 प्रतिशत तक और व्यावसायिक खोज पर 40 प्रतिशत तक लागत की वसूली की अनुमति देकर निवेश के जोखिम को कम करता है।

यह पहल एक व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत 2032 तक घरेलू तेल और गैस उत्पादन को तिगुना बढ़ाकर 85 मिलियन टन और राष्ट्रीय भंडार को दोगुना करके एक से दो बिलियन टन के बीच किया जा सकता है। लगभग 8 मिलियन टन उत्पादन के बराबर, अतिरिद्र 100 – 250 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस उपलब्ध कराने के लिए प्लग – एंड – प्ले आधार पर अपतटीय साझा बुनियादी ढाँचा बनाया जाएगा। ये सभी उपाय न केवल पहले से अटकी हुई खोजों का मुद्रीकरण करेंगे, बल्कि एक आत्मनिर्भर ईएंडपी इकोसिस्टम का निर्माण भी करेंगे, जहां स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की हिस्सेदारी आज के 25 – 30 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। यह आज़ादी के बाद से भारत का सबसे व्यापक अपस्ट्रीम सुधार है।

साथ ही, ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनकर उभरा है। भारत 2030 के लक्ष्य से पांच साल पहले ही 2025 तक 50% स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य तक पहुंच गया है। जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन प्रायोगिक स्तर से उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं। इथेनॉल मिश्रण और सीबीजी स्केल – अप एक नए ग्रामीण – औद्योगिक आधार का निर्माण कर रहे हैं। एलएनजी के बुनियादी ढांचे का विस्तार जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असैन्य परमाणु ऊर्जा को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान में, 10 नए परमाणु रिएक्टर चालू हैं, और भारत का लक्ष्य अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को दस गुना बढ़ाना है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने की भव्य योजना का हिस्सा है।

प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा हमारी औद्योगिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ऐसे समय में जब दुनिया लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्व , निकल और कोबाल्ट के सामरिक महत्व को पहचान रही है, भारत ने 1,200 से अधिक स्थलों पर अन्वेषण शुरू किया है और साझेदारी, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण का ढाँचा तैयार कर रहा है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, ईवी और उन्नत रक्षा क्षेत्र कभी भी बाहरी अवरोधों के अधीन न रहें।

राष्ट्रीय सुरक्षा लाल किला चार्टर का एक अन्य स्तंभ था। ऑपरेशन सिंदूर ने परमाणु ब्लैकमेल के युग का अंत करते हुए वास्तविक समय में भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और यह संदेश दिया कि आक्रमण का जवाब तेज़ी और कुशलता से दिया जाएगा। सिंधु जल संधि को स्थगित करना संप्रभुता का साहसिक दावा है। सबसे बढ़कर, मिशन सुदर्शन चक्र का अनावरण, युद्धभूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की रक्षा से प्रेरित है, जो मोदी की शैली सभ्यतागत प्रतीकवाद के अत्याधुनिक तकनीक से मेल का प्रतीक है।

एक बहुस्तरीय स्वदेशी सुरक्षा कवच भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों की साइबर, भौतिक और हाइब्रिड खतरों से रक्षा करेगा। प्रधानमंत्री ने हमारे लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करने वाले इंजनों के डिज़ाइन और निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय चुनौती जारी की है, और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और संस्थानों से संयोजन या असेंबली से ऑथरशिप तक की छलांग लगाने का आहवान किया है।

प्रधानमंत्री ने कठोर सत्यों से भी परहेज नहीं किया। उन्होंने उद्योग जगत और किसानों से आत्मनिर्भरता अपनाने और उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने का आग्रह किया। हालांकि भारत दुनिया की फार्मेसी है, जो वैश्विक टीकों का 60% का उत्पादन करता है, अब इसे नई दवाओं, टीकों और उपकरणों के क्षेत्र में भी अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। यह बायोई 3 नीति के तहत बायोफार्मा को निर्णायक बल देने के साथ – साथ है, जहाँ हमारी महत्वाकांक्षा ऐसी दवाओं का पेटेंट और उत्पादन करना है जो किफायती और विश्वस्तरीय दोनों हों।

घोषित किए गए कर और कानूनी सुधार भी उतने ही साहसिक हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1961 का आयकर अधिनियम, जो स्वयं उस युग का अवशेष है, अब बदला जा रहा है। नया आयकर विधेयक जटिलता को कम कर रहा है, 280 अनावश्यक धाराओं को समाप्त कर रहा है और 12 लाख रुपये तक की राहत प्रदान कर रहा है। फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत ने प्रणाली को पारदर्शी, कुशल और भ्रष्टाचार – मुक्त बना दिया है।

दिवाली तक लॉन्च किया जाने वाला अगली पीढ़ी का जीएसटी 2.0, दरों को और अधिक तर्कसंगत बनाएगा और अनुपालन को बढ़ावा देगा। 40,000 से ज्यादा अनावश्यक अनुपालनों को समाप्त करने, 1,500 से ज्यादा पुराने कानूनों को निरस्त करने और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के साथ, यह नेहरू के आर्थिक पिंजरे को तोड़ने जैसा है। ये सुधार केवल बैलेंस शीट में ही नहीं, बल्कि जीवन में भी सुधार लाते हैं। 25 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों तक पहुंचकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण – ने कल्याण में जवाबदेही को अंतर्निहित किया है और 25 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है।

रोज़गार पर फोकस को भी केंद्र में लाया गया है। पीएम विकसित भारत रोज़गार योजना 1 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लॉन्च की गई है। नए रोज़गार पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, नए रोज़गार के अवसरों का सृजन करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और इस कार्यक्रम का लक्ष्य लगभग 3.5 करोड़ युवा भारतीयों तक पहुंचना है।

महत्वाकांक्षा को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रधानमंत्री ने अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस निकाय को आर्थिक गतिविधियों के पूरे इकोसिस्टम को नया रूप देने के लिए बनाया गया है। इसका अधिदेश जितना साहसिक है, उतना ही लंबे अर्से से अपेक्षित भी है। हमारे स्टार्टअप्स और एमएसएमई पर बोझ डालने वाली अनुपालन लागत में कटौती करना, उद्यमों को निरंतर मनमानी कार्रवाई की छाया में रहने से छुटकारा दिलाना, तथा जटिल कानूनों को सरल, पूर्वानुमानित और व्यवस्थित ढांचे में ढालना।

15 अगस्त को घोषित सुधार, केवल अगले दिन की सुर्खियों के लिए नहीं, बल्कि 2047 के भारत से संबंधित हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने हमें याद दिलाया, दुनिया एक प्राचीन सभ्यता को – अपनी जड़ों को त्यागकर नहीं, बल्कि उनसे शक्ति प्राप्त करके आधुनिक शक्ति में तब्दील होते हुए देख रही है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर में सहकारी बैंकों के लिए आधार – आधारित प्रमाणीकरण ढांचा तैयार किया

- नए यूआईडीएआई ढांचे – आधार सेवाओं से 380 से अधिक सहकारी बैंक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित कर सकेंगे
- सहकारिता मंत्रालय, नाबार्ड और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद नया ढांचा तैयार किया गया है

शिमला। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में सहकारी बैंकों को आधार – आधारित प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए नया ढांचा तैयार किया है, जिससे बैंक की लोगों तक पहुंच बढ़ाने और डिजिटल समावेशन को काफी बढ़ावा मिलेगा।

यह ढांचा सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक – नाबार्ड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम – एनपीसीआई और सहकारी बैंकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद विकसित किया गया है। देश भर के सभी 34 राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) और 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के लिए यह सहायक होगा।

नई प्रणाली के तहत, आधार सेवा अपनाने की प्रक्रिया सरल और सस्ती बनाई गई है। इसमें केवल राज्यों के सहकारी बैंक ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियों (एयूए) और ई – केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसियों (केयूए) के रूप में पंजीकृत होंगे। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अपने राज्य सहकारी बैंकों के आधार प्रमाणीकरण अनुप्रयोग और सूचना प्रोद्यौगिकी ढ़ांचे का निर्बाध उपयोग कर सकेंगे। इससे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को अलग से आईटी प्रणाली विकसित करने या रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी जिससे बचत होगी और सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा।

इस ढांचे से, सहकारी बैंक आधार सेवाओं से ग्राहकों को तेज़, अधिक सुरक्षित और सुगम सेवा प्रदान कर सकेंगे। बायोमेट्रिक ई – केवाईसी और चेहरे की पहचान से खासकर ग्रामीण और अर्ध – शहरी क्षेत्रों में खाता खोलना आसान हो जाएगा। आधार के उपयोग से सब्सिडी और कल्याणकारी भुगतान सीधे ग्राहकों के सहकारी बैंक खातों में जमा किए जा सकेंगे ।

इसके अलावा यह ढांचा सहकारी बैंकों को आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) और आधार पेमेंट ब्रिज जैसी सेवाओं का विस्तार करने, डिजिटल लेनदेन व्यापक बनाने और सहकारी क्षेत्र में वित्तीय समावेशन बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।

आधार की पहुंच और उसके लाभ व्यापक बनाने में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में सहकारी बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी।

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए खाद्यान्न खरीद सुधारों पर चंडीगढ़ में चौथी राज्य-स्तरीय कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। खाद्यान्न खरीद पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता, पारदर्शिता और डिजिटल एकीकरण को मजबूत करने की चल रही राष्ट्रीय पहल के तहत, भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग डीएफपीडी ने 19 अगस्त को चंडीगढ़ में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू -कश्मीर के लिए चौथी राज्य-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला का उद्घाटन हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने संयुक्त सचिव नीति एवं एफसीआई, हरियाणा राज्य सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव और विभाग, भारतीय खाद्य निगम, तथा जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सरकारों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, आईएएस ने खरीद क्षेत्र में चुनौतियों के समाधान की दिशा में उठाए गए प्रगतिशील कदमों के लिए भारत सरकार और भारतीय खाद्य निगम को बधाई दी। अपने व्यक्तिगत अनुभव से उन्होंने पिछले 32 वर्षों में खरीद में हुई उल्लेखनीय वृद्धि पर भी प्रकाश डाला।

सीएमडी, एफसीआई, आशुतोष अग्निहोत्री, ने कहा कि राज्य सरकार के निरंतर सहयोग और समर्थन से, और भारत सरकार के साथ मिलकर काम करके, खरीद क्षेत्र में और भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि खरीद में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और उन्हें दूर

करना भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

इस कार्यक्रम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के 85 राज्य और जिला-स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की खरीद एजेंसियों, जैसे हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड HAFED, हरियाणा राज्य भंडारण निगम (HSWC), और हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, के प्रबंध निदेशक और अधिकारी शामिल थे। कार्यशाला में क्षमता निर्माण, ज्ञान साझा करने और खरीद नीतियों एवं डिजिटल सुधारों से व्यावहारिक परिचय कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

यह कार्यशाला खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खाद्यान्न खरीद करने वाले 18 प्रमुख राज्यों के लिए खरीद सुधारों पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशालाओं की एक व्यापक श्रृंखला का हिस्सा है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, प्रमुख नीतिगत उपायों के कार्यान्वयन में सुधार लाना और खरीद केंद्र स्व-मूल्यांकन पोर्टल पीसीएसएपी, बिना कुटाई वाले चावल का संयुक्त भौतिक सत्यापन जेपीवी, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल सीएफपीपी, केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल सीएफएसपी, एग्री-स्टैक, 10: टूटे चावल की व्यवस्था, खरीद एवं भंडारण नीति के लिए मार्ग अनुकूलन और स्कैन मॉड्यूल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को आसानी से अपनाना सुनिश्चित करना है।

उद्घाटन कार्यशाला 07.08.2025 को तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित की गई। दूसरी और तीसरी कार्यशालाएं छत्तीसगढ़ के लिए 13.08.2025 को रायपुर में और पंजाब के लिए 18.08.2025 को चंडीगढ़ में आयोजित की गई।

देश भर के प्रशिक्षु चिकित्सक कौशल निखारने को टांडा में होंगे एकत्रित

शिमला/शैल। राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा कालेज टांडा में देशभर के एमबीबीएस के प्रशिक्षु छात्र शैक्षणिक कौशल को निखारने के लिए एकत्रित होंगे। टांडा मेडिकल कालेज में 23 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह का पहला स्नातक चिकित्सा सम्मेलन मेडएस्केंड 2025 आयोजित किया जा रहा है।

यह जानकारी देते हुए सम्मेलन की समन्वयक डा. मोनिका पठानिया ने बताया कि उत्तर में जम्मू और कश्मीर से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक, भारत भर के विभिन्न कॉलेजों के नवोदित डॉक्टरों को विचारों का आदान-प्रदान करने, शैक्षणिक कौशल को निखारने और चिकित्सा के क्षेत्र में नए क्षितिज तलाशने के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे।

उन्होंने कहा कि मेडएस्केंड सम्मेलन के माध्यम से प्रशिक्षु चिकित्सकों को वैज्ञानिक शोध-पत्र प्रस्तुतियों, कार्यशालाओं, हैकथॉन और नेटवर्किंग जैसे कौशल को विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्ञान, सहयोग और विकास के अपने अनूठे मंच के साथ, मेडएस्केंड राज्य में स्नातक चिकित्सा शिक्षा के लिए एक नया अध्याय शुरू करता है।

उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में कई नए विकास और तकनीकी उन्नति हो रही है जैसे कि एक्सनोनेशियल थेरेपी, ग्रीन मेडिसिन, न्यूरोसाईंस, जेनोमिक्स तथा टेलिमेडिसिन जैसी तकनीकों से दूरस्थ उपचार तथा सलाहाकार सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं इस सभी के बारे में प्रशिक्षु चिकित्सकों को आज से ही तैयार करना अत्यंत जरूरी है ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ और उन्नतशील बनाने में अहम योगदान दे सकें।

डॉ. सन्नी शुक्ला बने हिमाचल भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) का नया अध्यक्ष डॉ. सन्नी शुक्ला को

बनाया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की। उनसे पहले तिलक राज शर्मा यह जिम्मेदारी संभाल रहे थे। डॉ. सन्नी शुक्ला लंबे समय से छात्र राजनीति और संगठनात्मक कार्यों से जुड़े रहे हैं। हमीरपुर जिले के खगल गांव से ताल्लुक रखने वाले डॉ. सन्नी शुक्ला ने अपनी शुरुआती शिक्षा सरकारी कॉलेज हमीरपुर से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से उच्च शिक्षा हासिल की। पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय की दीनदयाल उपाध्याय चेयर से पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा के साथ-साथ वे लगातार छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और संगठन को मजबूत करने में योगदान दिया।

शूलिनी विश्वविद्यालय की शोधकर्ता ने हिमालयी औषधीय पौधों से बनाए अनोखे स्वास्थ्य उत्पाद, दाखिल किए चार पेटेंट

शिमला/शैल। सतत् स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुये शूलिनी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंटल साइंसेज में सहायक प्रोफेसर एवं हर्बेरियम और ड्रग म्यूज़ियम की प्रभारी डॉ. राधा ने वर्ष 2025 में

हिमालयी औषधीय पौधों से विकसित पौधों पर आधारित स्वास्थ्य उत्पादों और पर्यावरण-अनुकूल निष्कर्षण विधियों के लिए चार पेटेंट दाखिल किये हैं। यह पहली बार है जब क्षेत्रीय जनजातीय उपचारों को वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर आधुनिक, एडिटिव-रहित फंक्शनल फूड्स और प्राकृतिक एंटीमाइक्रोबियल समाधानों में परिवर्तित किया गया है।

दाखिल पेटेंट्स में एक पोषक तत्वों से भरपूर जैम शामिल है, जो बॉम्बैक्स सीबा (सेमल) फूलों और सेब के पल्प से बनाया गया है। यह जैम आहार फाइबर, फिनॉल्स और फ्लेवोनॉयड्स से समृद्ध है तथा फूलों के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों का लाभ प्रदान करता है। इसमें किसी भी प्रकार के कृत्रिम प्रिज़र्वेटिव्स या रंगों का उपयोग नहीं किया गया है। एक अन्य पेटेंट आवेदन बॉम्बैक्स सीबा के फूलों से बने रेडी-टू-सर्व ड्रिंक से संबंधित है, जो इस पौधे के पारंपरिक शीतलन और पुनर्स्थापनात्मक गुणों को आधुनिक खाद्य विज्ञान से जोड़ते हुए बायोएक्टिव यौगिकों को सुविधाजनक रूप में प्रस्तुत करता है।

दो पेटेंट नवीन औषधीय पौधों के निष्कर्षण तरीकों से जुड़े हैं। इनमें से एक प्रिन्सेपिया यूटिलिस की पत्तियों से संबंधित है, जिससे ऐसे निष्कर्ष तैयार किये गये हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया, यहां तक कि दवा-प्रतिरोधी जीवाणुओं से भी लड़ने में सक्षम हैं। यह पहली बार है जब इस हिमालयी पौधे के ऐसे प्रभाव सामने आये हैं। दूसरा पेटेंट गिलोय (टीनोस्पोरा कॉर्डीफोलिया) की पत्तियों के लिये है, जिसमें कई एंटीमाइक्रोबियल यौगिकों को संरक्षित करते हुए पारंपरिक एंटीबायोटिक्स के लिए एक प्राकृतिक और पर्यावरण -अनुकूल विकल्प प्रस्तुत किया गया है।

डॉ. राधा ने कहा,'यह शोध उन पारंपरिक ज्ञानों को वैज्ञानिक प्रमाण देने की दिशा में एक कदम है, जो पीढ़ियों से मौखिक रूप से हस्तांतरित होते आये हैं। फील्ड डाक्यूमेंटेशन और प्रयोगशाला विश्लेषण को मिलाकर हमने पौधों पर आधारित स्वास्थ्य उत्पाद और पर्यावरण-अनुकूल निष्कर्षण विधियां विकसित की हैं, जो जनजातीय उपचारों को मान्य फंक्शनल फूड्स और प्राकृतिक एंटीमाइक्रोबियल समाधानों में बदलते हैं, जिससे आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय हिमालयी समुदायों दोनों को लाभ होगा।

ये पेटेंट आवेदन एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस जैसी गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करते हैं और साथ ही स्वदेशी ज्ञान की सुरक्षा तथा हिमालयी समुदायों के लिए औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण के माध्यम से आजीविका के अवसर भी उत्पन्न करते हैं।

ये पेटेंट डॉ. राधा के ऐतिहासिक एथ्नोबॉटैनिकल अध्ययन ''एथ्नोवेटरनरी मेडिसिन्स यूज़्ड बाय द ट्राइबल माइग्रेटरी शेफर्ड्स ऑफ नॉर्थवेस्टर्न हिमालय'' पर आधारित हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की गद्दी, किन्नौरा और जौनसारी जनजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 1,600 से अधिक औषधीय और खाद्य पौधों का दस्तावेजीकरण किया गया। यह शोध एडवांस्ड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के सहयोग से, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (देहरादून), डॉ.वाई.एस.परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री (नौनी), शूलिनी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ईस्ट कैरोलाइना यूनिवर्सिटी तथा यूनिवर्सिटी ऑफ वीगो, स्पेन के साथ मिलकर किया गया। अध्ययन ने पिक्रोराइज़ा कुर्रोआ, जेंटियाना कुर्रो और लिलियम पॉलीफाइलम जैसी दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर भी बल दिया।

सदियों पुराने हिमालयी उपचारों को वैज्ञानिक रूप से मान्य और वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक स्वास्थ्य समाधानों में परिवर्तित करके डॉ.राधा का कार्य परंपरा और नवाचार के बीच सेतु का निर्माण करता है और यह दर्शाता है कि कैसे स्वदेशी ज्ञान भविष्य की चिकित्सा को आकार दे सकता है।

मजठाई ग्राम पंचायत में वित्तीय समावेशन संतृप्ति एवं री-केवाईसी अभियान का सफल आयोजन

शिमला/शैल। वित्तीय सेवाएं विभाग एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देशभर में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलाये जा रहे वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के अंतर्गत मजठाई ग्राम पंचायत में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी रही जिसमे

60-70 लोगों ने अपनी उपस्थिती दर्ज़ कराई तथा उन्हें विभिन्न वित्तीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी उपलब्ध करायी गयी।

इस कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के उपमहाप्रबंधक पितांबर अग्रवाल, सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पितांबर अग्रवाल ने सामाजिक सुरक्षा स्कीम एवं Re-KYC की अनिवार्यता पर बल देते हुए उपस्थित जनों को डिजिटल वित्तीय लेनदेन में सावधानी एवं धोखाधड़ी से बचाव के उपायों के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया।

कार्यक्रम के दौरान एलडीएम कुलवंत राय ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एवं अटल पेंशन योजना (APY) के उद्देश्यों, पात्रता एवं लाभों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम के दौरान सहायक महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, संदीप अग्रवाल ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) व Re-KYC के बारें में लोगो को अवगत कराया। शिविर में विभिन्न बैंको द्वारा जनसुरक्षा स्कीम में पंजीकरण व Re-KYC की गयी। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के अभियान से ग्राम स्तर पर वित्तीय साक्षरता एवं बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। इस वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक शिविर आयोजित कर आमजन को बैंकिंग सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पेंशन योजनाओं, Re-KYC तथा डिजिटल सुरक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है।

2027 में भाजपा दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनायेगी: बिंदल

शिमला/शैल। भाजपा हिमाचल प्रदेश की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन जिला कार्यालय में किया गया जिसकी अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल द्वारा की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन महामंत्री डॉ. सिकंदर कुमार, संजीव कटवाल और पायल वैद्य उपस्थित रहें।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा प्रदेश में 2022 कि कांग्रेस सरकार एक आपदा सरकार बनकर आयी। आपदा के समय सरकार द्वारा भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया गया, 2000 से अधिक संस्थाओं को बंद कर दिया गया, झूठी गारंटियों से जनता को ठगा गया और अब तो पशु मित्र जैसे पदों को जारी कर प्रदेश भर में बेरोजगारों के जख्मों पर नमक छिड़का गया। जहां सरकार ने 58 साल की पक्की नौकरी का वादा किया था आज यह सरकार 3 साल में केवल 30000 नौकरियां ही दे भाई वह भी पक्की नहीं कच्ची।

भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने बैठक के बारे में बताते हुए कहा कि प्रथम सत्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने भाजपा की पिछली प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा किए गए कार्यक्रमों का लेखा-जोखा नए अधिकारियों के सामने रखा जिसमें सेवा सुशासन और गरीब कल्याण महा अभियान, सेवा पखवाड़ा, तिरंगा यात्रा जैसे प्रमुख अभियानों के बारे में बताया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने बताया कि लोकसभा सीटों की दृष्टि से हमने चारों सीटों पर विजय प्राप्त की जिसमें 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्रों पर हमने बढ़त हासिल की। डॉ. बिंदल ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को साथ लेते हुए दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी इसके लिए हम संकल्पित है। बिंदल ने 2047 विकसित भारत का संकल्प भी लिया, और साथ ही वर्तमान कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकने का संकल्प भी लिया।

इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से आने वाले पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनाव में कमर कसने का आहवान किया और इन चुनाव में भाजपा द्वारा चयनित उम्मीदवारों को जिताकर प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, पार्षद, जिला परिषद के पदों पर बैठने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम का भाव रखते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए हर कार्य को धरातल पर उतरेंगे।

रणधीर शर्मा ने बताया कि भाजपा का सेवा पखवाड़ा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक चलेगा इसके संयोजक प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल होंगे, उनके साथ सह संयोजक सचिव सुमित शर्मा, अमित ठाकुर, तिलक राज एवं डॉ. संजय रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, जहां पूरे देश भर में हम संघ शताब्दी वर्ष मनाएंगे। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्तर पर संयोजक के रूप में उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा देखेंगे उनके साथ सह संयोजक सचिव वंदना योगी, कुसुम सदरेट, प्रियंता शर्मा और शिशु भाई धर्मा देखेंगे।

भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय एवं योजनाओं और सामाजिक कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत चर्चा की और मीडिया प्रबंधन को लेकर विशेष जानकारी दी। इसके साथ-साथ सह प्रभारी संजय टंडन ने सोशल मीडिया के बारे में कार्यकर्ताओं को विस्तृत जानकारी दी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने समापन सत्र में प्रश्न उत्तर लेते हुए कार्यशाला का समापन किया।

इस बैठक में सभी नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी, 17 जिला अध्यक्ष, 171 मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे।

एसडीआरएफ़ के तहत वित्तीय वर्ष 2025 – 2026 के लिए 441.60 करोड़ की धनराशि आवंटित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप द्वारा लोकसभा में पुछे गये सवालों के उत्तर में गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के परामर्श से, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 5 टीमों को मानसून-2025 के लिए कुल्लू, शिमला, सिरमौर, लाहौल और स्पीति, किन्नौर में पहले से तैनात किया गया था। इसके अलावा, वर्तमान मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन के मद्देनजर, राज्य में बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 13 टीमों को तैनात किया गया है।

केंद्रीय मंत्री के बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को एसडीआरएफ़ के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 441.60 करोड़ (397.60 करोड़ केंद्रीय अंश + 44.00 करोड़ राज्य अंश) की धनराशि आवंटित की गई है जिसके केंद्रीय अंश से 198.80 करोड़ रुपये की पहली किस्त राज्य को जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य के एसडीआरएफ़ खाते में 1 अप्रैल, 2025 को 81.10 करोड़ रुपये का शुरुआती शेष उपलब्ध बताया गया है। साथ ही, वर्ष 2024 की बाढ़ एवं भूस्खलन के लिए एनडीआरफ से 107.15 करोड़ रुपये जारी किये गए।

इस मानसून के दौरान बाढ़, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए एक आईएमसीटी का गठन किया। आईएमसीटी ने 18 से 21 जुलाई, 2025 तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

केंद्र सरकार ने पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण निधि के दिशानिर्देशों के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लिए 2006.40 करोड़ रुपये के परिव्यय को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, 451.44 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त भी दिनांक 7 जुलाई, 2025 को जारी कर दी गई है।

नित्यानंद राय ने बताया कि राज्य में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और मूसलाधार वर्षा की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) रुड़की, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) पुणे, भूविज्ञानी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर के विशेषज्ञों की एक बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय टीम गठित की गई है।

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 12.08.2025 तक 226 जन जीवन की हानि और 2,703 पशु धन की क्षति हुई है तथा 2535 मकान क्षतिग्रस्त हुये हैं।

आईआईआईटी ऊना में 7वां दीक्षांत समारोह सम्पन्न

शिमला/शैल। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), ऊना ने 23 अगस्त 2025 को अपना 7वां दीक्षांत समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया, यह संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। इस अवसर पर एक पीएच.डी. शोधार्थी और 135 बी.टेक. स्नातकों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।

लोकसभा के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने IIIT ऊना के 7वें दीक्षांत समारोह में अतिथि के रूप में उपस्थिति दी और स्नातक छात्रों, उनके गर्वित अभिभावकों तथा समर्पित शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने दीक्षांत समारोह को एक शैक्षिक यात्रा में मील का पत्थर बताते हुए राष्ट्रीय योगदान की महत्ता पर बल दिया। 23 अगस्त 2023 को भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान-3 लैंडिंग की वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने इस दिन को अब 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस' के रूप में मनाए जाने की प्रतीकात्मक महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण में प्रगति, जैसे कि आदित्य-एल1 और विक्रम-S मिशनों के साथ-साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। इस युग को 'सुनहरा युग' और युवाओं को 'सुनहरी पीढ़ी' करार देते हुए उन्होंने भारत के विकासशील स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सराहना की, जिसमें 1.85 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें 48% महिलाओं द्वारा संचालित हैं।

प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF) एवम् पूर्व अध्यक्ष एआईसीटीई, ने स्नातक छात्रों, पदक विजेताओं और उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने IIIT ऊना की पिछले एक दशक में हुई तेज़ प्रगति की सराहना की, जो 2014 में पीपीपी मोड में अपनी स्थापना से लेकर आज एक सजीव और पर्यावरण-अनुकूल परिसर बन चुका है, इस परिसर में 800 छात्र और 35 संकाय सदस्य निवास करते हैं।

प्रो. सहस्रबुद्धे ने तेज़ी से बदलते तकनीकी परिदृश्य, यानी एआई, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, पर विचार व्यक्त किए और छात्रों के लिए आजीवन सीखने वाले और ज़िम्मेदार वैश्विक नागरिक बनने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के चंद्र और आदित्य मिशनों का उल्लेख देते हुए विज्ञान, अर्थव्यवस्था, रक्षा और अंतरिक्ष में भारत के वृद्धिशील वैश्विक नेतृत्व पर प्रकाश डाला।

प्रोफेसर मनीष गौर, निदेशक, IIIT ऊना ने पीएच.डी. शोधार्थी एवं स्नातक छात्रों की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने उनकी शैक्षणिक यात्रा के दौरान सामने आई चुनौतियों का उल्लेख किया, और उनकी दृढ़ता और समर्पण की सराहना की।

कुल 136 छात्रों ने दीक्षांत समारोह में भाग लिया, जिनमें 1 पीएच.डी. अभ्यर्थी, कंप्यूटिंग स्कूल से 55 बी.टेक छात्र, इलेक्ट्रॉनिक्स स्कूल से 47 बी.टेक छात्र, और सूचना प्रौद्योगिकी से 33 बी.टेक छात्र सम्मिलित थे।

बी.टेक (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग) में शुभम झा ने 9.37 सीजीपीए के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त किया, हर्षिल दीप सिंह ने 9.18 सीजीपीए के साथ रजत पदक अर्जित किया, और यश कमल सक्सेना ने 9.03 सीजीपीए के साथ कांस्य पदक हासिल किया। बी.टेक (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग) में अक्रोश विक्रम शुक्ला ने 9.76 सीजीपीए के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त किया, इसके बाद केशव कुमार अग्रवाल ने 9.42 सीजीपीए के साथ रजत पदक और ऋषव मिश्रा ने 9.12 सीजीपीए के साथ कांस्य पदक प्राप्त किया। बी.टेक (सूचना प्रौद्योगिकी) से दीपक ने 9.29 सीजीपीए के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त किया, अनुराग टंडन ने 8.51 सीजीपीए के साथ रजत पदक और साहिल ने 8.48 सीजीपीए के साथ कांस्य पदक प्राप्त किया। IIIT ऊना के कुलसचिव गौरव टंडन द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

आपदा के समय कांग्रेस सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है:रणधीर

शिमला/शैल। भाजपा मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि आपदा के समय भले नुकसान छोटा हो पर गरीबों के लिए नुकसान ज्यादा ही होता है। फील्ड स्टाफ का काम मौके पर जाना, नुकसान का जायजा लेना और फौरी राहत देना होता है पर जब तक एक विधायक फील्ड स्टाफ या पटवारी को फोन नहीं करता वह मौके पर नहीं जाते हैं, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आपदा के समय यह सभी प्रो एक्टिव होने चाहिए।

रणधीर शर्मा ने सरकार की कार्य प्रणाली पर सवालिया चिन्ह उठाते हुए कहा आपदा के समय वर्तमान सरकार बचती दिखाई दी, उनके प्रतिनिधि कहते हैं कि बादल फटने का पता नहीं लगता। पर हम सरकार से सवाल करते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में होने वाली बारिश का तो पता होता है? आज से पहले सरकार ने कभी पूर्व एवं पूर्ण योजना पर काम किया?

रणधीर शर्मा ने कहा कि हम कमियां नहीं बताएंगे तो सुधार कैसे होगा आलोचना तो व्यवस्था तो एक भाग है। आपदा के समय एक बात तो स्पष्ट रही की सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, शायद नुकसान विपक्ष के विधानसभा क्षेत्रों का हुआ है इसलिए सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। आपदा के समय राजस्व विभाग का बड़ा रोल होता है और राजस्व मंत्री के ब्यान स्पष्ट करते हैं कि वह इस आपदा के समय गंभीर नहीं थे, साथ ही लोक निर्माण विभाग भी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और संकट की घड़ी में विभाग मंत्री विक्रमादित्य ही आपदा के समय घूमने चले गए, हम पूछना चाहते हैं कि आपदा से महत्वपूर्ण कार्य क्या हो सकता है ?

शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। भाजपा के समय ठेकेदार कहते थे की जेसीबी लगा दो टेंडर का इंतजार मत करो पैसे तो आ ही जाएंगे, पर वर्तमान कांग्रेस के सरकार के समय यह हालत हो गई है कि टेंडर लगने के बाद भी ठेकेदार काम नहीं कर रहे। क्योंकि उनको अपने बिलों के भुगतान की चिंता है।

विश्वसनीयता समाप्त होने का एक और उदाहरण है कि हिमाचल की जनता मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे जमा नहीं करवा रही अपितु सीधा जाकर या नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के माध्यम से पीड़ितों को धनराशि प्राप्त करवा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार में चलती गुटबाजी को लेकर भी जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की जिस मंत्री से नहीं बनती उसके विभाग को पैसा बजट प्रावधान में कटौती करने के बाद दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका पीड़ितों को राहत पहुंचाने में कठिनाइयां आ रही है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या भाजपा सुक्खू की चुनौति के जवाब में ई.डी. में दस्तक देगी?

शिमला/शैल। क्या भाजपा सुक्खू सरकार के प्रति ईमानदार गंभीरता से आक्रामक है या उसकी आक्रामकता एक राजनीतिक रस्म अदायगी भर है? यह सवाल इसलिये उठ रहा है कि सुक्खू सरकार जिस तरह से कर्ज पर आश्रित हो गयी है वह भविष्य के लिये एक बड़े संकट का न्योता साबित होगी। क्योंकि बढ़ते कर्ज का सबसे पहला और बड़ा असर यह होता है कि सरकार को अपने प्रतिबद्ध खर्चो में सबसे पहले कटौती करनी पड़ती है। इन प्रतिबद्ध खर्चो में सबसे पहले कर्मचारी वर्ग आता है। उसमें स्थायी नियमित रोजगार को कम करके अस्थायी और आउटसोर्स का सहारा लेना पड़ता है। जब से प्रदेश में आउटसोर्स का चलन शुरू हुआ है तभी से उसी अनुपात में नियमित रोजगार में कटौती हुई है। बढ़ते कर्ज का दूसरा प्रभाव जन सुविधाओं पर पड़ता है। सरकार नियमित सुविधाओं से कर्ज के अनुपात में ही पीछे हटती जाती है। इस सरकार पर कर्ज पर आश्रित होने का जितना आरोप लगता जा रहा है उसी अनुपात में यह सरकार पूर्व सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाती जा रही है। लेकिन पूर्व के सरकार के नेतृत्व द्वारा इस कुप्रबंधन का कोई कड़ा जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस सरकार पर विपक्ष भ्रष्टाचार के जितने आरोप लगा रहा है वह सब अपने में गंभीर हैं। लेकिन उन आरोपों पर अब तक एक भी आरोप पत्र विधिवत राज्यपाल को सौंपकर किसी जांच की मांग नहीं की गयी है। बल्कि जो आरोप देहरा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे होशियार सिंह ने वाकायदा विधिवत शिकायत के रूप में महामहिम राज्यपाल को सौंपे हैं उनकी जांच की मांग को लेकर पूरी भाजपा खामोश खड़ी है और राजभवन भी शायद उस शिकायत को भूल ही गया है। बल्कि एचआरटीसी कि ई-वर्कशॉप को लेकर नादौन में खरीदी गई जमीन में घपला होने के जो आरोप विधायक सुधीर शर्मा ने लगाये थे उन आरोपों पर भी पूरी भाजपा ने मौन साध लिया है। ऐसे और भी कई उदाहरण है जो भाजपा नेतृत्व से इस दिशा में जवाब मांगते हैं।

इस परिदृश्य में भाजपा की आक्रामकता को लेकर आम आदमी भी इसे एक रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं है। भाजपा की इस नियत और नीति पर अब कुछ सवाल उठने लग पड़े हैं। क्योंकि भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के दौरान अपने उम्मीदवार को विजयी बना लिया था उस समय भाजपा पर धन बल के सहारे सरकार गिराने का आरोप लगा था। इस आरोप के बाद कांग्रेस और भाजपा में जिस तरह के आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर चला और अदालत तक भी पहुंच गया उसका अंतिम परिणाम कोई सामने नहीं आया है। यह सही है कि इस समय राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। इसी नाजुक्ता के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का अभी तक विकल्प नहीं ला पायी है। यह माना जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय परिदृश्य का असर प्रदेश पर भी पड़ रहा है। प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी में क्षेत्रीय असन्तुलन के आरोप मुखरित होने लग पड़े हैं। इसलिये प्रदेश सरकार के प्रति भाजपा की आक्रामकता पर भी सवाल उठने शुरू हो गये हैं। बल्कि यह कहा जाने लगा है की मुख्यमंत्री सुक्खू की सियासी चालों ने कांग्रेस से ज्यादा भाजपा को पंगु बना दिया है और भ्रष्टाचार के आरोपों पर ई.डी. में जाने की चुनौती दे रहे हैं।

रोजगार पर स्वतः .....पृष्ठ 1 का शेष

सरकार कहां खड़ी है तो इन्हीं आंकड़ों से सरकार की सारी कारगुजारी सामने आ जाती है। क्योंकि प्रदेश में बेरोजगारों का आंकड़ा दस लाख से ऊपर है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारों का आंकड़ा 46% तक जा पहुंचा है। यह सामने आ चुका है कि इस सरकार ने आउटसोर्स पर पुराने लगे बहुत सारे युवाओं को हटाकर नई कंपनियों के माध्यम से नये लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया है। आउटसोर्स का मामला अदालत तक भी पहुंच गया था। ऐसे में रोजगार के मामले में सरकार को बहुत ज्यादा चौकस रहना होगा। इस संबंध में स्वत: विरोधी आंकड़े सरकार द्वारा परोसे जाना विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर देते हैं और रोजगार ही प्रदेश का मुख्य मुद्दा है। आंकड़ों के विरोधाभास पर तंत्र की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्योंकि विपक्ष तो इस स्वत: विरोध को सरकार के खिलाफ एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा।

एक साल में बिजली सब्सिडी छोड़ने से प्रदेश सरकार ने बचाए 59 लाख

शिमला/शैल। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में बिजली सब्सिडी और स्मार्ट मीटर का मुद्दा प्रमुखता से उठा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने उपभोक्ताओं की चिंताओं को मुखरता से उठाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार का किसी उपभोक्ता की सब्सिडी बंद करने का कोई इरादा नहीं है। चाहे किसी उपभोक्ता के पास एक मीटर हो या अधिक, उन्हें पूर्व की तरह सब्सिडी मिलती रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने केवल अपील की है कि जो लोग स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ना चाहें, वे ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की मौजूदा योजना जारी रहेगी और भविष्य में इसे 300 यूनिट तक बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। इस पर अंतिम निर्णय राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 12 से 15 हज़ार लोगों ने बिजली सबसिडी छोड़ी है।

विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने बिजली सब्सिडी के वितरण और स्मार्ट मीटरों को लेकर सवाल किए। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया और भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने पूछा कि कंपनियों को दी जा रही सब्सिडियों का डाटा सरकार किस आधार पर रखती है और एक से अधिक मीटर वाले उपभोक्ताओं को किस तरह सब्सिडी दी जाती है। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक किसी उपभोक्ता की सब्सिडी बंद नहीं की गई है।

वहीं भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार भविष्य में एक से अधिक मीटर रखने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी रोक सकती है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है और योजना जस की तस जारी रहेगी।

भाजपा विधायक डॉ. हंसराज ने स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों की स्थिति को लेकर प्रश्न उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या स्मार्ट मीटर आने से बिल काटने वाले कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसी भी कर्मचारी की नौकरी पर संकट नहीं आयेगा और सभी को विभाग के अन्य कार्यो में समायोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी जानकारी दी कि गत वर्ष से 20 फरवरी 2025 तक बिजली सब्सिडी छोड़ने से प्रदेश सरकार को 59 लाख रुपये का आर्थिक लाभ हुआ है। वहीं कैबिनेट रैंक प्राप्त नेताओं के बिजली बिलों पर इसी अवधि में 17.95 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

स्मार्ट मीटर लगाने की प्रगति पर मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला शहर, धर्मशाला शहर और शिमला जोन के तहत आने वाले क्षेत्रों में अब तक 6,52,955 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। शेष क्षेत्रों में फरवरी 2026 तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा।